

पहला कॉलम



सीबीआई के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे केजरीवाल

नई दिल्ली । दिल्ली शराब कांड में तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने सीबीआई की गिरफ्तारी को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। बता दें कि बीते दिनों सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। इसके बाद केजरीवाल ने अपनी याचिका में सीबीआई की गिरफ्तारी को अवैध बताया है। साथ ही केजरीवाल ने दिल्ली की एक अदालत के 26 जून के आदेश को भी चुनौती दी है, इसमें उन्हें तीन दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा गया था। केजरीवाल को शराब घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में राउज एक्वेन्यू कोर्ट ने 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजा। केजरीवाल को सीबीआई ने तीन दिन की हिरासत में पृच्छताछ के बाद अदालत में पेश किया था। सीबीआई ने केजरीवाल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में अपना भेजने का अनुरोध कर कहा कि "जांच और न्याय के हित में" उनकी हिरासत जरूरी है। सीबीआई की याचिका मंजूर कर विशेष न्यायाधीश सुनयना शर्मा ने कहा था कि केजरीवाल को 12 जुलाई को अदालत में पेश किया जाए।

केन्द्रीय कर्मचारियों को फ्रीज किए गए डीए का पैसा जारी कर सकती मोदी सरकार

नई दिल्ली । देश के लाखों सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिल सकता है। कोरोनाकाल में फ्रीज किए गए महंगाई भरे ते (डीए) के पैसे को मोदी सरकार अब जारी कर सकती है। महामारी की आपदा में साल 2020 से 2021 तक मोदी सरकार ने 18 महीने का डीए का पैसा फ्रीज किया था। इस लेकर कई बार कर्मचारी संगठनों ने मांग की, लेकिन इस बार उम्मीद जाहिर की गई है कि मोदी सरकार अपने कर्मचारियों को तोहफा दे सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार कर्मचारी संगठनों ने वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के साथ पीएम मोदी को पास भी अपनी सिफारिश भेजी है। इस बार 18 महीने के बकाया डीए के लिए केन्द्रीय कर्मचारियों की संयुक्त त सलाहकार मशीनरी राष्ट्रीय परिषद (कर्मचारी पक्ष) के सचिव शिव गोपाल मिश्र ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि कोरोनाकाल में सरकारी कर्मचारियों ने अपना दायित्व बखूबी निभाया और अब उन्हें रोके गए डीए का भुगतान होना चाहिए। केन्द्र सरकार हर साल 2 बार महंगाई भत्ता बढ़ाती है। एक बार जनवरी में और दूसरा जुलाई में। 2020 में कोरोना महामारी की वजह से आर्थिक चुनौतियां आईं और तब तीन बार का डीए फ्रीज कर दिया गया था। इसके पहले जनवरी में भारतीय प्रतीक्ष मजदूर संघ के महासचिव मुकेश सिंह ने वित्तमंत्री सीतारमण को पत्र लिखकर जनवरी 2020 से जून 2021 के बीच फ्रीज किए गए 18 महीने के डीए को जारी करने का आग्रह किया था। उन्होंने मोदी सरकार से कोरोनाकाल के दौरान कर्मचारियों के योगदान और बलिदान की दुहाई भी दी थी।

लोनावाला में वॉटर फाल में बह गया पूरा परिवार, 3 की मौत....दो लापता

मुंबई । मुंबई से सटे लोनावाला में झुंडियां मनाए गए पूरा परिवार खत्म हो लोनावाला में छुट्टी मनाए गए परिवार के 5 सदस्य वॉटर फाल में बह गए हैं। ये वॉटर फाल भूसी बांध के पीछे एक पहाड़ी पर बना हुआ था। इस घटना का एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें उस क्षण को कैद किया गया है जब सात लोगों का एक परिवार तेज धारा में बह गया था। मृतकों की पहचान शाहिस्ता लियाकत अंसारी (36), अमिमा आदिल अंसारी (13) और उमेश आदिल अंसारी (8) के रूप में की है। साथ ही तेज बहाव में लापता हुए कुछ लोगों के शव जलाशय के एक किनारे से बरामद किया गया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि अदरान सभाहत अंसारी (4) और मारिया अकौल अंसारी (9) अभी भी लापता हैं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि अंसारी परिवार के सदस्य भूशी बांध के पास झरना देखने गए थे, लेकिन इलाक़े में भारी बारिश के कारण पानी का प्रवाह अचानक बढ़ गया और वे परिवार के 5 सदस्य बह गए। जिस परिवार के साथ यह हादसा हुआ है उसके रिश्तेदार का कहना है कि कुछ रिश्तेदार शायद के लिए मुंबई से आए थे। जो परिवार पानी में बहा है, वहां पुणे के सैयद नगर का रहने वाला है। इसकी जानकारी पुणे एसपी पंकज देशमुख ने दी है। पुलिस के मुताबिक, पर्यटक झरने में फिसल गए और नीचे की ओर जलाशय में डूब गए। झरने के बीच में खाने-पीने की दुकानें देखी गईं, जहां पर्यटक सुरक्षा को लेकर किसी भी चिंता से बेफिक्र दिखाई दिए थे। क्षेत्र में पर्यटकों को जाने से रोकने के लिए कोई सुरक्षा व्यवस्था भी नजर नहीं आई।



देश में तीन नए आपराधिक कानून लागू

आज से आईपीसी को भूल जाओ....बीएनएस हुआ लागू

नई दिल्ली । (एजेंसी)

देश में 1 जुलाई 2024 से तीन नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। अब आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) इंडियन एक्टिविटी एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएनएसए) लागू हो गया है। पिछले साल ही संसद में इन तीनों कानून बन गए थे। अब नए कानूनों के लागू होने के साथ ही औपनिवेशिक काल के कानूनों का अंत हो गया है। कई अपराध थे जिन्हें आईपीसी में परिभाषित नहीं किया गया था। इसमें यह नहीं बताया गया था कि कौन से अपराध

आतंकवाद की श्रेणी में आएंगे। नए कानून में भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा को खतरा पैदा करने को आतंकवाद की श्रेणी में रखा गया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 113 में इसका वर्णन है। इसमें भारतीय मुद्रा की गतिविधियों के लिए उग्रकैद या फिर मौत की सजा भी हो सकती है। आतंकवादी गतिविधियों के लिए उग्रकैद या फिर मौत की सजा भी हो सकती है। कानून के मुताबिक आतंकी सजिश रचने के लिए पांच साल से लेकर उग्रकैद तक की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा आतंकी संगठन से जुड़ने पर उग्रकैद और जुर्माने का प्रावधान है। आतंकीयों को छिपाने पर तीन साल से लेकर उग्रकैद की सजा होगी है। इसके अलावा जुर्माना भी लगाया जा

सकता है। वहीं भारतीय न्याय संहिता में राजद्रोह को समाप्त किया गया है। वहीं भारत की एकता और अखंडता को खतरा पहुंचाने वाले कृत्यों को देशद्रोह में शामिल किया गया है। इसके लिए बीएनएस की धारा 152 लगाई जाएगी। वहीं आईपीसी में मौब लिंगिंग का भी जिक्र नहीं था। अब नए कानून में अपराध के लिए उग्रकैद से लेकर मौत तक की सजा हो सकती है। इस बीएनएस की धारा 103 (2) में शामिल किया गया है।

बीएनएस में आईपीसी की कौन सी धाराएं बदली
हत्या के लिए आईपीसी में धारा 302 थी जो कि बीएनएस में धारा 101 हो गई है। हत्या का प्रयास का मुकदमा जो धारा

307 के तहत दर्ज होता था, अब धारा 109 के तहत दर्ज होगा। गैर इरादतन हत्या के लिए धारा 105 लागू होगी जो कि आईपीसी में धारा 304 थी। दहेज हत्या से जुड़ी धारा 80 होगी जो कि आईपीसी में धारा 304बी थी। चोरी के लिए अब धारा 303 में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। आईपीसी के तहत धारा 379 में चोरी का मुकदमा दर्ज होता था। इस तरह रप की धारा 376 से बदलकर अब 64 हो गई है। छेड़छाड़ का मुकदमा धारा 74 के तहत दर्ज होगा। धोखाधड़ी का केस धारा 420 की जगह अब 318 के तहत दर्ज

होगा। लारपवाही से मौत का मामला धारा 106 के तहत आएगा जो कि पहले 304ए में आता था। आपराधिक षड्यंत्र के लिए धारा 120बी की जगह धारा 61 लागू होगी। मानहानि के लिए धारा 499, 500 की जगह अब 356 लागू होगी। लूट और डकैती के लिए क्रमशः धारा 309 और धारा 310 होगी।

अब दंड की जगह..... त्वरित सुनवाई होकर न्याय

तीनों कानूनों के लागू होने पर शाह

नई दिल्ली । (एजेंसी)

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देशभर में नए आपराधिक कानून लागू होने के बीच कहा कि अब तीन नए कानूनों के कार्यान्वयन के बाद दंड की जगह न्याय होगा और त्वरित सुनवाई होगी। केन्द्रीय मंत्री शाह ने नए आपराधिक कानूनों के संबंध में कहा कि आजादी के 77 साल बाद आपराधिक न्याय प्रणाली स्वदेशी हो रही है और यह भारतीय लोकतंत्र के आधार पर चलेगी। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम

(बीएनएस) 2023 सोमवार से पूरे देश में प्रभावी हो गए। इन तीनों कानून ने ब्रिटिश कालीन कानूनों क्रमशः भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ली है। केन्द्रीय मंत्री शाह ने कहा, तीनों आपराधिक न्याय कानूनों के कार्यान्वयन से सबसे आधुनिक आपराधिक न्याय प्रणाली की स्थापना होगी। उन्होंने कहा कि इन कानूनों के लागू होने से दंड की जगह न्याय मिलेगा और देरी की जगह त्वरित न्याय होगा। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश कालीन पुरानी व्यवस्था में केवल पुलिस के

अधिकार सुरक्षित थे, लेकिन अब पीड़ितों और शिकायतकर्ताओं के अधिकार सुरक्षित होने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन तीनों आपराधिक न्याय कानूनों पर चार वर्ष से अधिक समय तक विचार-विमर्श हुआ है। उन्होंने उम्मीद जाहिर कि नए आपराधिक न्याय कानूनों के तहत दोषसिद्धि दर 90 प्रतिशत तक होगी और अपराधों में कमी आएगी। केन्द्रीय गृह मंत्री शाह ने देश के सभी दलों से राजनीतिक से ऊपर उठकर आपराधिक न्याय कानूनों का समर्थन करने की अपील की और कहा कि यदि विपक्ष के किसी भी नेता को नए आपराधिक कानूनों को लेकर कोई



चिंता है, तब वह उसे मिलने के लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि नए आपराधिक न्याय प्रणाली के बारे में 22.5 लाख से अधिक पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षित करने के लिए 12,000 से अधिक 'मास्टर' प्रशिक्षक तैनात किए गए और नए कानून के तहत पहला केस न्यायिकरण में रविवार रात 12 बजकर 10 मिनट पर बाइक चोरी का दर्ज किया गया।

जेल में बंद बरामूला से लोकसभा चुनाव जीते इंजीनियर राशिद को मिली राहत

25 जुलाई को सांसद के रूप में शपथ लेने की एनआईए ने दी सहमति

नई दिल्ली । (एजेंसी)

एनआईए ने सोमवार को जेल में बंद कश्मीरी नेता और इंजीनियर शेख अब्दुल राशिद, को 25 जुलाई को सांसद के रूप में शपथ लेने के लिए सहमति दे दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंद्रजीत सिंह कल यानी मंगलवार को इसका आदेश जारी करेंगे। जम्मू-कश्मीर के बरामूला क्षेत्र से लोकसभा चुनाव जीतने वाले अब्दुल राशिद जिन्हें 2017 के जम्मू-कश्मीर आतंकी फंडिंग मामले में गिरफ्तार किया गया है। राशिद ने लोकसभा में सांसद की शपथ लेने और अपने संसदीय कार्य करने के लिए अंतरिम जमानत की मांग अदालत से की

थी। विशेष अदालत ने 22 जून को मामले को स्थगित कर दिया था और एनआईए को अपना जवाब पेश करने को कहा था। एनआईए के वकील ने कहा कि सहमति कुछ शर्तों के अधीन है, जिसमें मीडिया के साथ बातचीत न करना भी शामिल है। राशिद ने नेशनल कॉन्फिडेंस नेता और जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला को हराकर बरामूला से लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की है। राशिद को जम्मू-कश्मीर आतंकी फंडिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था। वर्तमान में वह तिहाड़ जेल में बंद हैं। इस मामले में राशिद की सलिसता कश्मीरी व्यापारी जहूर वताली की जांच के दौरान सामने आई थी, जिससे



एनआईए ने आतंकवादी समूहों और कश्मीरी अलगाववादियों को फंडिंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में जिन नामों को शामिल किया है उनमें यासीन मलिक, लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद और हिजबुल मुजाहिदीन प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन शामिल हैं।

माइक का रिमोट आसन के पास नहीं होता है: ओम बिरला

राहुल गांधी का माइक बंद के लगे आरोप पर नाराज हुए स्पीकर

नई दिल्ली । (एजेंसी)

कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जब सदन में अपनी बात कहते हैं तो माइक बंद कर दिया जाता है? ये आरोपी कांग्रेस अक्सर लगाती है। विगत दिवस लोकसभा की पिछली कार्यवाही के दौरान गौरव गोगोई और दीपेंद्र हुड्डा ने यह मुद्दा उठाया। कांग्रेस के इन आरोपों पर अब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने विपक्षी सांसदों को संबोधित करते हुए कहा कि बाहर आरोप लगाते हैं कि पीठसीन अधिकारी माइक बंद कर देते हैं। आपको कई साल हो गए हैं और अनुभव भी है। आप

पुराने सदन में थे और नए सदन में भी हैं। आपको पता होगा कि माइक का रिमोट आसन के पास नहीं होता है, चाहे किसी भी दल का सदस्य हो। इसलिए इस तरह का आरोप नहीं है? स्पीकर ओम बिरला ने इसके बाद कांग्रेस सांसद के. सुरेश का भी जिक्र करते हुए कहा, कि सुरेश जी भी यहां बैठते हैं, लेकिन उनसे पूछें कि वहां कोई माइक का कंट्रोल है क्या? इसके बाद उन्होंने खुद उनसे पूछ लिया कि स्पीकर के आसन के पास कोई माइक होता है क्या? इस पर सुरेश ने इनकार किया तो फिर बिरला ने कहा कि देखो कोई बटन नहीं है। आसन से

सिर्फ व्यवस्था दी जाती है। हम माइक बंद नहीं करते हैं। दरअसल इससे पहले कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि लोकसभा में नीट पेपर लीक पर चर्चा की मांग को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का माइक बंद कर दिया गया था। कांग्रेस ने एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा-जहां एक ओर नरेंद्र मोदी नीट पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, उस वक्त विपक्ष के नेता राहुल गांधी युवाओं की आवाज सदन में उठा रहे हैं लेकिन, ऐसे गंभीर मुद्दे पर माइक बंद करने जैसी ओझी हरकत करके युवाओं की आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा है।

पीएम मोदी के रूस दौरे से पहले उठी मास्को में भव्य मंदिर बनाने की मांग

प्रधानमंत्री 8 जुलाई को रूस के दौरे पर, राष्ट्रपति पुतिन से करेंगे मुलाकात

नई दिल्ली । (एजेंसी)

रूस और यूक्रेन जंग के बीच पीएम नरेंद्र मोदी 8 जुलाई को रूस के दौरे पर जा रहे हैं। पीएम वहां राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत करेंगे। पीएम मोदी के इस दौरे को भारत-रूस संबंधों को मजबूती मिलने की उम्मीद है। इस बीच वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों ने मांग की है कि वह मास्को में एक हिन्दू मंदिर बनाना चाहते हैं। भारत और नेपाल में हिन्दू आबादी बहुसंख्यक है। रूस में बहुसंख्यक आबादी ईसाई की होने के बावजूद कुछ जगहों पर छोटे मंदिर

बनाए गए हैं, लेकिन यह मुख्य रूप से सामुदायिक केंद्र की तरह ही काम करते हैं। ऐसे में अब राजधानी मास्को में मंदिर बनाने की मांग तेज होने लगी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पीएम मोदी के रूस दौरे से पहले वहां इंडियन बिजनेस अलायंस और इंडियन नेशनल कल्चरल सेंटर ने भव्य हिन्दू मंदिर बनाने को लेकर बैठक की। इस समूह के अध्यक्ष ने कहा कि मास्को में बनने वाला ये हिन्दू मंदिर न केवल भारतीयों के लिए एकता और आकर्षण का केंद्र बनेगा, बल्कि भारत-रूस के बीच मजबूत संबंधों का प्रतीक भी बनेगा। इससे पहले पीएम मोदी ने इस साल

14 फरवरी को संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया था। यह मंदिर यूएई द्वारा दी जमीन पर बोचासनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्थान ने बनाया था। यह मंदिर भले ही हिंदू धर्म का है, लेकिन इसमें मुस्लिम, जैन और बौद्ध धर्म के लोगों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। 27 एकड़ जमीन में फैले इस मंदिर के लिए यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद जायद अल नाहयान ने जमीन दान में दी थी। जो करीब 700 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है। इस मंदिर के मुख्य आर्किटेक्ट ईसाई थे,



जब इस प्रोजेक्ट के मैनेजर सिख समुदाय, वाला कंपनी पारसी की थी, जिसके डिजाइनर बौद्ध थे। इस मंदिर को बनाने डायरेक्टर जैन समुदाय से थे।

रोजगार, किसान, गांव और मध्यम वर्ग पर फोकस हो बजट



डॉ. उमेश प्रताप सिंह

मध्यवर्ग को राहत देने के क्रम में सरकार को दो और प्रमुख बातों पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। प्रथम, वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन की बहाली या पेंशन व्यवस्था में सुधार और द्वितीय, आठवां वेतन आयोग का गठन। यह न सिर्फ वेतनभोगी वर्ग की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए बल्कि अर्थव्यवस्था में उपभोग और आर्थिक समृद्धि को गति देने के लिए आवश्यक है।

बजट सरकार के वित्त का सबसे विस्तृत व्यौरा होता है जिसमें सभी स्रोतों से प्राप्त राजस्व और सभी मदों पर किया गया व्यय सम्मिलित होता है। आव-व्यय के विवरण सरकार के समष्टिभावी आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के हिसाब से तैयार किये जाते हैं। इसलिए बजट सरकारी नीतियों की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण होता है। बजट के पहले भाग में सामान्य आर्थिक सर्वेक्षण और नीतियों का व्यौरा होता है और दूसरे भाग में आगामी वित्त वर्ष के लिए प्रत्यक्ष और परोक्ष करों के प्रस्ताव रखे जाते हैं। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) आने के बाद अप्रत्यक्ष करों के संदर्भ में निर्णय जीएसटी कार्टिसिल ही लेती है इसलिए अब आम लोगों के लिए बजट की उत्सुकता पहले की अपेक्षा कम हो गई है। हाँ, जो लोग प्रत्यक्ष कर दे रहे हैं, उनके लिए अवश्य इसकी उत्सुकता अधिक होती है। सरकार के व्यय करने के कार्यक्रमों और नीतियों के संदर्भ में भी अब जनता अधिक जागरूक है। उच्च संवृद्धि, तेजी से बढ़ता विनिर्माण क्षेत्र, निर्यात मुद्रास्फीति और बजट अनुमानों की तुलना में राजकोषीय घाटे में कमी से लगता है कि इस समय देश में आर्थिक हालात अच्छे हैं। हालांकि रुपये का थोड़ा सा अवमूल्यन हुआ है और भुगतान संतुलन का चालू खाता घाटा जीडीपी का लगभग 0.7% है। परन्तु विदेशी मुद्रा भंडार 665.8 बिलियन डॉलर के सर्वाधिक उच्च स्तर पर पहुँच गया है। तो फिर बजट में मोदी सरकार के सामने चुनौती इस विकास को बनाए रखने और मुद्रास्फीति, विशेष रूप से खाद्य मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के मुद्दे को संबोधित करने की है। स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी सेवाएं दोगुना खर्चीली हो गई हैं जिन्हें हरेक व्यक्ति प्रभावित हो रहा है। परन्तु आधिकारिक मुद्रास्फीति दर 5 प्रतिशत से भी कम है। ग्रामीण क्षेत्रों में आय नहीं बढ़ रही है। बजट में अन्य गतिविधियों के अतिरिक्त अलग से रोजगार सृजित करने वाले क्षेत्रों एवं व्यवसायों पर विशेष रूप से फोकस करना चाहिए। 'डेज ऑफ़ ड्रिगिंग बिजनेस' में सुधार भले हुआ हो, प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरण से भ्रष्टाचार कम होने का दावा भले ही किया जा रहा, परन्तु जमीनी वास्तविकता यह है कि सुगमता एवं स्वतंत्रता के साथ व्यवसाय करने की जटिलता कम नहीं हुई है, राज्य एवं जिला स्तरों पर भ्रष्टाचार बढ़ गया है और लगातार बढ़ती अफसरशाही ने इन्फेक्टिव राज को मजबूत किया है। बजट में कर में छूट और सामाजिक व्यय में वृद्धि की उम्मीद है। पिछले बजटों में पूंजीगत व्यय पर ध्यान केंद्रित

किया गया, जिससे जीडीपी को बढ़ावा मिला। परन्तु पूंजीगत व्यय रोजगार पैदा करने और आय बढ़ाने में सक्षम नहीं रहा है इसलिए उपभोग व्यय में कमी आयी। सरकार ने जिस प्रकार से विभिन्न मंत्रालयों का बंटवारा किया है और पुरानी नीतियों को जारी रखने का संकेत दिया है उससे नीतियों में बजट के दौरान बहुत बदलाव की संभावना नहीं है। आशा है कि सरकार राजकोषीय संतुलन को साधते हुए पूंजीगत व्यय में कोई कमी नहीं लाएगी, क्योंकि अर्थव्यवस्था में आर्थिक समृद्धि को तेज करने के लिए यह आवश्यक है। साथ ही उन क्षेत्रों और उद्योगों में निवेश बढ़ाने पर अधिक फोकस करेगी जहाँ रोजगार सृजन की संभावना अधिक है।

रोजगार और आय बढ़ाने के ठोस उपायों की आवश्यकता

पिछले कुछ वर्षों में राजकोषीय नीति के दो मुख्य उद्देश्य रहे हैं, सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे में निवेश करके पूंजी निर्माण में वृद्धि करना और राजकोषीय घाटे को वित्त वर्ष 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद के 6.8 प्रतिशत से घटाकर वित्त वर्ष 2025-26 तक 4.5 प्रतिशत करना है। सरकार ने पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर और विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों पर व्यय को कम करके अपने व्यय करने की प्रवृत्ति में थोड़ा बदलाव किया। समग्र बजट में पूंजीगत व्यय का हिस्सा कोरोना काल के लगभग 12 प्रतिशत से बढ़कर अब 23 प्रतिशत से अधिक हो गया है। केंद्र सरकार के लिए सकल घरेलू उत्पाद के लिए पूंजीगत व्यय का अनुपात

वित्त वर्ष 2019-20 में 1.7 प्रतिशत से वित्त वर्ष 2023-24 में लगातार बढ़कर 3.2 प्रतिशत हो गया। सापेक्षिक रूप से, खाद्य सब्सिडी, मनरेगा, और पीएम किसान जैसे कुछ प्रत्यक्ष कल्याण कार्यक्रमों के लिए आवंटित धन 1.7 प्रतिशत से घटकर जीडीपी का 1.2 प्रतिशत हो गया। इन वर्षों में, पूंजी निर्माण तेजी से बढ़ा है - वित्त वर्ष 2019-20 और वित्त वर्ष 2023-24 के बीच इसमें 29.5 प्रतिशत की संघीय वृद्धि हुई। इसी अवधि के दौरान, उपभोग, जो अर्थव्यवस्था का लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा है, में केवल 17.5 प्रतिशत की संघीय वृद्धि हुई। अर्थव्यवस्था के विभिन्न वर्गों से उपभोग की मांग के बीच गंभीर विरोधाभास के भी प्रमाण हैं। आर्थिक रूप से मजबूत वर्गों ने विभिन्न प्रीमियम वस्तुओं और सेवाओं की मजबूत मांग दिखाई है, जबकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की मांग अभी तक कोविड के झटके से उबर नहीं पाई है। पूंजी निर्माण और निर्माण गतिविधियों में विस्तार रोजगार पैदा करने के बजाय अधिक पूंजी और प्रौद्योगिकी संचालित रहा है। पूंजीगत व्यय के लिए सरकार के लगातार ढबाव के बावजूद, उपभोग और मांग में मजबूत वृद्धि नहीं होने के कारण निजी निवेश में कोई भी सार्थक वृद्धि नहीं हो रही है। इसलिए, बजट में मांग को बढ़ावा देने के लिए सरकारी व्यय के पुनः आवंटन की एक उचित नीति की आवश्यकता है। चुनाव में झटका खाया मोदी सरकार द्वारा इसीलिए अगले बजट में आवस्य, ग्रामीण सड़कें, आजीविका बढ़ाने आदि जैसे कार्यक्रमों के लिए अधिक धन आवंटित किया जा

सकता है या मांग को बढ़ावा देने के लिए घरेलू क्षेत्र पर करों में छूट दी जा सकती है, जो आवश्यक भी है।

रोजगार पर फोकस

चुनाव का सन्देश बड़ा स्पष्ट है कि जब तक आर्थिक समृद्धि का लाभ समाज के निचले वर्ग के वर्तियों और बेरोजगारों तक नहीं पहुंचता है तब तक वे भारत के सिर्फ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने को लेकर संतुष्ट नहीं हो सकते। बल्कि उनके लिए रोजगार के अवसरों के लिए सरकार को प्रयास करना ही होगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनकी वास्तविक आय में लगातार वृद्धि हो। आर्थिक वृद्धि के साथ तेज गति से उत्पादक रोजगार तैयार करने पर बजट को फोकस करना चाहिए। रोजगार में वृद्धि कार्यकारी आयु के लोगों में वृद्धि की दर से अधिक होनी चाहिए।

रोजगार सृजन के लिए सिर्फ आर्थिक संवृद्धि पर निर्भर रहने की जगह तेज रोजगार सृजन के द्वारा आर्थिक संवृद्धि तेज करने की रणनीति पर चलना चाहिए। सरकार पहले ही निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए जीडीपी के तीन प्रतिशत के बराबर पूंजीगत व्यय कर रही है, अब बेहतर कारोबारी वातावरण तैयार करने और निजी निवेश को प्रोत्साहित कर भर में ध्यान देना चाहिए। भौतिक और डिजिटल अधोसंरचना में सुधार तथा ई-कॉमर्स एवं डिजिटल भुगतान प्रणालियों के तेजी से विस्तार का उपयोग करके अधिक रोजगार सृजन पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

मध्य वर्ग को कर में राहत आवश्यक

सापेक्षिक रूप से देखा जाए तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों को मिलाकर मध्य वर्ग पर करों का भार सबसे अधिक है। हाल के वर्षों में व्यक्तिगत आयकरदाता के लिए वास्तविक कर भार में बढ़ोत्तरी हुई है। इस समय आय कर का योगदान निगम कर से अधिक हो गया है। वित्त वर्ष 2023-24 में शुद्ध निगम कर 9.11 लाख करोड़ रुपये था, जबकि शुद्ध आयकर 10.44 लाख करोड़ रुपये था। इसीलिए आय कर में छूट की अपेक्षा कई वर्ष से की जा रही है। 5 लाख से 20 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले करदाताओं को राहत देने की आवश्यकता है। अभी वे लोग 5 लाख से 15 लाख तक 5 से 20 प्रतिशत की कर दर और 15 लाख से ऊपर आय वाले करदाता 30 प्रतिशत की कर दर का सामना कर रहे हैं। वेतनभोगी वर्ग के लिए उनके वेतन और ग्रेजुएट पर आयकर छूट की अधिकतम सीमा को पर्याप्त रूप से बढ़ाना चाहिए। सरकारी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती की राशि को बढ़ाकर एक लाख रुपए कर देना चाहिए।...

संपादकीय

विश्व चैम्पियन इंडिया

भारत ने टी-20 विश्व कप चैम्पियन बनकर आईसीसी ट्रॉफियों से लंबे समय से चली आ रही दूरी को आखिरकार, खत्म कर दिया। भारत ने आखिरी बार आईसीसी ट्रॉफी 2013 में चैम्पियंस ट्रॉफी के तौर पर जीती थी। यहाँ तक विश्व कप की बात है तो 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में वनडे विश्व कप में चैम्पियन बना था। इसके बाद करीब 13 साल के समय में भारतीय टीम कई बार नई ऊंचाईयें छूती नजर आई पर आखिरी समय में लड़खड़ा गई अंदाज में खेलने का फैसला किया। पिछले साल वनडे विश्व कप और विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप में हमें इस तरह की स्थिति का ही सामना करना पड़ा। वनडे विश्व कप के फाइनल में हारने के बाद तो टी-20 में रोहित की कप्तानी पर भी सवाल उठने लगे थे। पर बीसीसीआई ने करीब सात महीने पहले रोहित को ही कप्तान बनाने का फैसला किया। इसी दौरान अजित अग्रकर भी मुख्य चयनकर्ता बन गए। इस तिकड़ी के बीच बेहतर रिश्तों ने टीम को चैम्पियन टीम में बदल दिया। द्रविड़ और रोहित की कोच और कप्तान की जोड़ी ने टी-20 को उसके ही अंदाज में खेलने का फैसला किया। इस विश्व कप के दौरान मुश्किल हालात में भी आक्रामक अंदाज से खेलने की सोच साफ दिखी। इस विश्व कप के फाइनल के हीरो विराट कोहली को ही लें। वह आम तौर पर विकेट पर थोड़ा रुक कर धीरे-धीरे गियर बदलने के लिए जाने जाते हैं पर पहली ही गेंद से आक्रामक रुक अपनाने के फैसले के बाद वह इसमें ज्यादातर मैचों में बड़ा स्कोर बनाने में सफल नहीं हुए। विराट के रोहित के साथ पारी शुरू करने की आलोचना भी हुई पर टीम प्रबंधन इन आलोचनाओं से प्रभावित हुए धीरे धीरे योजना पर आगे बढ़ता रहा। भारत की इस सफलता की खूबी किसी एक खिलाड़ी का प्रदर्शन नहीं रहा। भारत के चैम्पियन बनने में जितनी अहमियत विराट की पारी की है, उतनी ही अहमियत अक्षर पटेल की पारी की भी है। बुमराह, अर्शदीप और हार्दिक पांडे? का गेंदबाजी भी चैम्पियन बनने में अहम रही। सूर्यकुमार यादव का बंडेड़ी लाइन पर आखिरी ओवर में डेविड मिलर का लपका शानदार कैच भी खास रहा। सही मायनों में द्रविड़ और रोहित द्वारा टीम को एक सूत्र में पिरोने का यह कमांड है पर द्रविड़ का कोच के तौर पर कार्यकाल खत्म होने, रोहित और विराट द्वारा अंतरराष्ट्रीय टी-20 क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा के बाद अब आने वाले कोच की जिम्मेदारी होगी कि वह इस तरह जिम्मेदारी निभाने वाली यंग ब्रिगेड को तैयार करे।

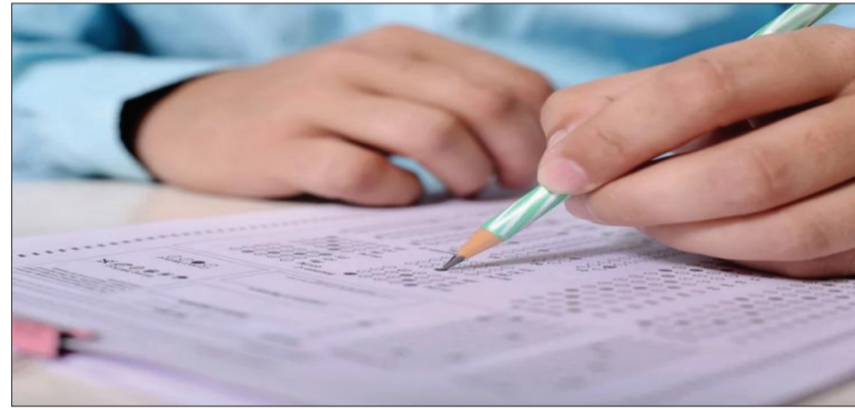
वितन-मनम

हर जीव में व्याप्त नारायण

वैदिक साहित्य से हम जानते हैं कि परम-पुरुष नारायण प्रत्येक जीव के बाहर तथा भीतर निवास करने वाले हैं। वे भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों जगतों में विद्यमान हैं। यद्यपि वे बहुत दूर हैं, फिर भी हमारे निकट हैं- आसीनो दूर ब्रजति शयानो याति सर्वतरु हम भौतिक इन्द्रियों से न तो उन्हें देख पाते हैं, न समझ पाते हैं अतएव वैदिक भाषा में कहा गया है कि उन्हें समझने में हमारा भौतिक मन तथा इन्द्रियाँ असमर्थ हैं। किन्तु जिसने, भक्ति में कृष्णभावनामृत का अभ्यास करते हुए, अपने मन-इन्द्रियों को शुद्ध कर लिया है, वह उन्हें निरन्तर देख सकता है। ब्रह्मसंहिता के अनुसार परमेर के लिए जिस भक्त में प्रेम उपज चुका है, वह निरन्तर उनके दर्शन कर सकता है। और भगवद्गीता में कहा गया है कि उन्हें केवल भक्ति द्वारा देखा-समझा जा सकता है। भगवान् सबके हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हैं। तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि वे बड़े हैं? नहीं। वास्तव में वे एक हैं। जैसे सूर्य मध्यह्न समय अपने स्थान पर रहता है, लेकिन यदि कोई पांच हजार मील की दूरी पर घूमे और पूछे कि सूर्य कहाँ है, तो सभी कहेंगे कि वह उसके सिर पर चमक रहा है। इस उदाहरण का अर्थ है कि यद्यपि भगवान् अविभाजित हैं, लेकिन इस प्रकार स्थित हैं मानो विभाजित होवैदिक साहित्य में यह भी कहा गया है कि अपनी सर्वशक्तिमत्ता द्वारा एक विष्णु सर्वत्र विद्यमान हैं। जिस तरह एक सूर्य को प्रतीति अनेक स्थानों में होती है। यद्यपि परमेर प्रत्येक जीव के पालनकर्ता हैं, किन्तु प्रलय के समय सबका भक्षण भी कर जाते हैं। सृष्टि रची जाती है, तो वे सबको मूल स्थिति से विकसित करते हैं और प्रलय के समय सबको निगल जाते हैं। वैदिक शास्त्र पुष्टि करते हैं कि वे समस्त जीवों के मूल तथा आश्रय-स्थल हैं। सृष्टि के बाद सारी वस्तुएँ उनकी सर्वशक्तिमत्ता पर टिकी रहती हैं और प्रलय बाद सारी वस्तुएँ पुनः उन्हें निष्क्रमण पाते के लिए लौट आती हैं।

जो

इ-टोड़ की सरकार अब भरोसे के लायक भी नहीं बची है। युवाओं के साथ खेल इस तरह से खेला जा रहा है कि परिस्थिति अब सुनहरे सपने के बजाय आजादी के अमृत काल में विषयान को विवश हो रहे हैं। दुर्दांत अपराधी हैं, जो युवाओं के वर्तमान और भविष्य के साथ खेल रहे हैं, लेकिन उस रहस्यमय व्यवस्था को लेकर क्या कहा जाए जो दावा तो आजादी के अमृतकाल और अच्छे दिनों का करती है? ऐसे में कहाँ गए उसके वो दावे और वादे, जिसकी विज्ञापन पर सत्ता की मद में आमद होकर सियासतदारों ने एक दशक के करीब करोड़ों-अरबों रुपए बना लिए, लेकिन युवाओं को मिला तो सिर्फ खोखले वादे और पेपर लीक वाली सरकारी व्यवस्था है। पेपर लीक किसी एक सरकार में उपजी कोई फौरी समस्या नहीं है, लेकिन बनी-बनाई व्यवस्था की ध्वजियाँ उड़ाने का काम आजादी के अमृतकाल के नाम पर हो, तो शोक सभा व्यवस्था और व्यवस्थापक दोनों के नाम पर होना चाहिए। शब्दों का मायाजाल थोड़ा चुभने वाला हो सकता है, लेकिन परीक्षा का जो भ्रमजाल बनाकर युवाओं का धीरे-धीरे, उनका वर्तमान, उनका समय और उनका परीक्षा फॉर्म के नाम पर पैसा



बर्बाद किया जा रहा उससे कहीं कम है सरकारी तंत्र के लिए इन शब्दों की चुभना। दर्द जब बेइतहा उठने लगे तो उसकी वेदना में सरकार और उनका सरकारी तंत्र दोनों बँसेमानी लगता है। वर्तमान समय का आलम कुछ यूँ ही है। सरकारी तंत्र ने नेट की परीक्षा रद्द करने का एक फैसला जारी किया है। वह भी आजादी के अमृतकाल वाले लैटर हैड पर। अब जरा सोचिए आजादी का ये कैसा अमृत महोत्सव है? जहाँ युवाओं को पिलाया जहर का घूंट जा रहा। निःसन्देह युवाओं की वेदना, पीड़ा और रुदन किसी विष का पान करने से कम नहीं है। पहले नीट की परीक्षा में धांधली और अब नेट की परीक्षा रद्द। उसके बाद लगातार राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं जैसे सीआईएसआर नेट का स्थगित होना। ये साबित करता है कि देश में सरकारी पात्रता परीक्षाओं का हाल ऐसा है, जैसे किसी मुहल्ले के स्कूल की परीक्षा। सच पृष्ठ पर तो इतनी धांधली तो राज्यस्तरीय परीक्षाओं में नहीं

होती। जितना अब राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में धांधली हो रही है। नीट परीक्षा का आलम यह हुआ कि औने-पौने हिसाब से नंबर बाँट दिया गया। नीट परीक्षा में नंबर डाले तब से प्रसाद में बाँटे गए जैसे किसी सत्यनारायण कथा के बाद प्रसाद। वैसे महंगाई के इस दौर में प्रसाद भी सोच-समझकर बाँटा और बनवाया जाता है, लेकिन हमारे देश की शिक्षा-व्यवस्था है। जहाँ सोच-समझकर लगाता है कोई काम नहीं हो रहा। परीक्षा फॉर्म के नाम पर करोड़ों-अरबों रुपए बार-बार वसूले जाते हैं। साल-दो साल के भीतर परीक्षा फॉर्म के लिए लगाने वाली फीस बढ़ा दी जाती है, लेकिन युवाओं के जीवन में परीक्षा के बाद कोई सार्थक परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। तभी तो युवाओं का भविष्य अंधकार में है और मजबूत और सुरक्षित धांधली में जिसके देश की सरकार है। वो नेट जैसी परीक्षा को रद्द करवाकर जांच सीबीआई को सौंपकर ही भारत माता भाग्य विधाता की धुन में मदमस्त है।

हेमंत सोरेन की जमानत ने झामुमो में जगाई नयी आस



सोरेन ने इसी साल जनवरी में हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किए जाने के बाद राजनीति में प्रवेश करने का फैसला किया था। गणेश विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव में उनकी जीत से यह संदेश मिलता है कि झारखंड की जनता और पार्टी कार्यकर्ता राजनीति में उनके प्रवेश के फैसले की आतुरता से प्रतीक्षा कर रहे थे। उल्लेखनीय है कि कल्पना सोरेन उच्च शिक्षित महिला हैं और विगत 5 माहों में झारखंड की राजनीति में उनका दौर तेजी से बढ़ा है। हेमंत सोरेन के जेल में रहने के दौरान कल्पना सोरेन ने न केवल झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाए रखा बल्कि उन्होंने विपक्षी इंडिया गठबंधन की रैलियों में विरोधी दलों के नेताओं के साथ मंच भी साझा किया। चुनावी रैलियों में मर्यादित भाषा में संवाद अदायगी की उनकी प्रभावी शैली से विरोधी दलों के नेताओं और आम जनता के बीच जगह बनाने में उन्हें पर्याप्त सफलता मिली। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राजनीति में

उनकी सक्रियता से झारखंड में पार्टी का जनाधार बढ़ना तय है। वे हेमंत सोरेन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं और उन्हें हर जगह अपनी प्रभावी उपस्थिति का अहसास कराने में सफलता मिल रही है। जमानत पर हेमंत सोरेन की रिहाई के बाद अब यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या उनके मन में वर्तमान मुख्यमंत्री चम्पई सोरेन से कुर्सी खाली करा कर पुनः मुख्यमंत्री पद पर आसीन होने की महत्वाकांक्षा जाग सकती है। अभी ऐसे कोई आसार नहीं आ रहे हैं। मुख्यमंत्री चम्पई सोरेन से उनके परिवारिक संबंध हैं और इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है कि चम्पई सोरेन आगे भी पूरी तरह से हेमंत सोरेन के प्रति वफादार बने रहेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि पुनः मुख्यमंत्री पद की बागडोर संभालने के बजाय हेमंत सोरेन इसी साल होने वाले झारखंड विधानसभा के चुनावों में पार्टी की विजय सुनिश्चित करने पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित

राजस्थान, मध्यप्रदेश जैसे तमाम राज्य हैं। जहाँ की प्रादेशिक परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक जैसी समस्याएँ आम बात रही हैं, लेकिन अब राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएँ और एनटीए जैसा बड़ा संभूतन अगर परीक्षाएँ बेहतर तरीके से नहीं करवा पा रहा है तो उसकी प्रसांगिकता पर सवाल उठाने लाजिमी हैं। वैसे भी नेट की परीक्षा केवल सरकारी खजाना भरने के अलावा ज्यादा महत्व रखता नहीं, क्योंकि हर छह महीने में 10 लाख के करीब अभ्यर्थियों फॉर्म भरते हैं और परीक्षा के बाद का लब्धोलुआब सिर्फ एक सर्टिफिकेट होता है। जिसके बाद न तो पीएचडी में एडमिशन मिलता और न ही अस्पिटलेंट प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति। ऐसे में रहनुमाई व्यवस्था और उनके सिपह-सालारों से सवाल यही है कि क्या उनके बच्चों के भविष्य के साथ ऐसे खिलवाड़ होता तो उनके आँखों का पानी मरा रह पाता? सवाल बहुतेरे हैं, लेकिन जवाब देने से अब सत्ता और सत्ताधोश डरते नहीं या देना चाहते नहीं हैं। तभी तो कई मंत्रबा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी सवाल उठता है। वैसे अब बात सिर्फ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं, जीवन जीने की स्वतंत्रता और जीवन में सफल होने की चुनौती बहुत बड़ी हो चली है, क्योंकि सरकारी नौकरी ही आज की सामाजिक व्यवस्था में सर्वस्वीकार्य है और उसके लिए आयोजित परीक्षाएँ ही धांधली की शिकार है। सियासतदार, युवाओं का दर्द समझ नहीं सकते, क्योंकि उनके बच्चों का यह राजनीतिक पद पर है या बिजनेस में हैं। वरना विदेश में नेताजी की कमाई से उच्च गुणवत्ता की शिक्षा अर्जित कर रहे हैं। ऐसे में एक कहावत याद आती है कि, जाके पाँव न फटी बिवाई, वो क्या जाने पेर पाई!



हेल्थ इश्योरेंस कंपनी निवा बूपा ने 3,000 करोड़ रुपये के आईपीओ के लिए जमा कराए ड्राफ्ट पेपर

मुंबई । देश की बड़ी हेल्थ इश्योरेंस कंपनियों में से एक निवा बूपा की ओर से सोमवार को 3,000 करोड़ रुपये के इनिशियल पब्लिक ऑफर (आईपीओ) के लिए ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (डीआरएचपी) भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (सेबी) के पास जमा करा दिए गए हैं। जानकारी के मुताबिक, निवा बूपा हेल्थ इश्योरेंस का आईपीओ फेश इश्यू और ओएफएस का मिश्रण होगा। इसमें 800 करोड़ रुपये का फेश इश्यू और 2,200 करोड़ रुपये का ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) होगा। इस ओएफएस में कंपनी के मौजूदा शेयरधारक भाग लेंगे। ओएफएस के तहत 320 करोड़ रुपये के शेयर बूपा सिंगापुर होल्डिंग्स पीटीई और 1,880 करोड़ रुपये के शेयर फेटल टोन एलएलपी की ओर से बेचे जाएंगे। बूपा सिंगापुर होल्डिंग्स की कंपनी में 62.27 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जबकि फेटल टोन एलएलपी की 27.86 प्रतिशत हिस्सेदारी है। रिपोर्ट्स में बताया गया कि मॉर्निंग स्टैन्ली इंडिया, कोटक महिंद्रा कैपिटल, एक्सिस कैपिटल, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज और एचडीएफसी बैंक को कंपनी की ओर से हायर किया गया है। निवा बूपा दूसरी स्टैंड-अलोन हेल्थ इश्योरेंस कंपनी होगी, जो कि भारतीय स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने वाली है। पिछले वर्ष सितंबर में निजी प्राइवेट इक्विटी फर्म टू नॉर्थ ने निवा बूपा हेल्थ इश्योरेंस में अपनी 20 प्रतिशत हिस्सेदारी 2,700 करोड़ रुपये में पार्टनर कंपनी बूपा को 13,500 करोड़ रुपये के वैल्यूएशन पर बेच दी थी।

अब यूपी के चार एक्सप्रैस-वे पर मिलेगी ई-ट्रैकिंग चार्जिंग की सुविधा

अडानी टोल एनर्जी ई-मोबिलिटी लिमिटेड को सौंपी निर्माण की जिम्मेदारी

लखनऊ । यूपी की योगी आदित्यनाथ की सरकार ईवी को प्रमोट कर रही है। ईवी की संख्या में इजाफा को देखते हुए चार्जिंग स्टेशनों को लेकर भी सरकार गंभीर है। अब यूपी के एक्सप्रैस-वे पर ई-ट्रैकिंग के लिए चार्जिंग सुविधाओं को बढ़ा जा रहा है। प्रदेश के चार प्रमुख एक्सप्रैस-वे पर चार्जिंग स्टेशन बनाने की योजना बनाई है। यूपी के आगरा-लखनऊ एव सांप्रस-वे, पूर्वांचल एव सांप्रस-वे, बुंदेलखंड एव सांप्रस-वे और गोरखपुर लिंक एव सांप्रस-वे पर 26 चार्जिंग स्टेशन बनाने की योजना है। यूपी ईवी पॉलिसी 2022 के तहत प्रदेश के प्रमुख एक्सप्रैस-वे पर नए चार्जिंग स्टेशनों को स्थापित किया जा रहा है। पूर्वांचल एव सांप्रस-वे, बुंदेलखंड एव सांप्रस-वे और गोरखपुर लिंक एव सांप्रस-वे पर 14 जनसुविधा परिसरों का भी निर्माण किया जाएगा जिससे यहां से गुजरने वाले वाहनों को राहत मिलेगी। साथ ही, ईवी बसों को भी लंबी दूरी के मार्गों पर चलाया जाएगा। इससे परंपरागत इंधन पर निर्भरता को कम किया जा सकेगा। यूपी के चार प्रमुख एक्सप्रैस-वे पर चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। आगरा-लखनऊ एक्सप्रैस-वे पर आठ नए चार्जिंग स्टेशन बनेंगे। वहीं 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रैस-वे और 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रैस-वे पर भी 8-8 नए चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। 91 किलोमीटर लंबे गोरखपुर लिंक एक्सप्रैस-वे पर दो ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाने की योजना है। एक्सप्रैस-वे पर ईवी चार्जिंग स्टेशनों के निर्माण के लिए एजेंसी का चयन कर लिया है। मेसर्स अडानी टोल एनर्जी ई-मोबिलिटी लिमिटेड को निर्माण की जिम्मेदारी दी गई है। वाहनों के चार्जिंग के रेट को भी जल्द तय किया जाएगा। इसके अलावा चारों एक्सप्रैस-वे पर 14 जनसुविधा केंद्रों के निर्माण का कार्य किया जा रहा है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रैस-वे पर दो जनसुविधा परिसर का पीपीपी मॉडल पर विकास के लिए भारत पेट्रोलियम लिमिटेड का चयन किया गया है। अन्य 12 परिसरों का विकास ईपीसी मॉडल पर यूपीडी की ओर से कराया जा रहा है।

इस हफ्ते खुलेंगे 2,700 करोड़ रुपये के आईपीओ, दो कंपनियों की लिस्टिंग

मुंबई :-

आईपीओ बाजार में तेजी बनी हुई है। एक के बाद एक कंपनियां अपना आईपीओ लेकर आ रही हैं। इस हफ्ते मेनबोर्ड कैटेगरी में एमक्योर फार्मास्युटिकल्स और बंसल वायर इंडस्ट्रीज का इनिशियल पब्लिक ऑफर (आईपीओ) आ रहा है। एमक्योर फार्मास्युटिकल्स का आईपीओ 3 जुलाई को आम जनता के लिए खुलेगा। इस आईपीओ के जरिए कंपनी करीब 1,952 करोड़ रुपये जुटाएगी। यह आईपीओ फेश इश्यू और ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) का मिश्रण होगा। इस

आईपीओ में 800 करोड़ रुपये का फेश इश्यू और 1,152 करोड़ रुपये ओएफएस होगा। एमक्योर फार्मास्युटिकल्स का आईपीओ 3 से लेकर 5 जुलाई तक नाम निवेशकों के लिए खुलेगा। इसका प्राइस बैंड 960 रुपये से लेकर 1,008 रुपये प्रति शेयर रखा गया है। इसका लिस्टिंग 14 शेयरों का तय किया गया है। शेयर की लिस्टिंग 10 जुलाई को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) पर हो सकती है। एमक्योर फार्मास्युटिकल्स, शार्क टैंक में जज रह चुकीं नमिता थापर से जुड़ी कंपनी है। कंपनी को 1981 में स्थापित किया गया था। कंपनी

भारत मोबाइल फोन निर्यात में चीन और वियतनाम को दे रहा टक्कर

निर्यात वित्त वर्ष 2024 में 40 फीसदी से बढ़कर 15.6 अरब डॉलर हुआ

नई दिल्ली। मोबाइल फोन निर्यात के मामले में भारत, चीन और वियतनाम को टक्कर दे रहा है। वर्ष 2024 में चीन और वियतनाम के मोबाइल निर्यात में पिछले साल की तुलना में 2.78 फीसदी और 17.6 फीसदी की गिरावट आई, जबकि भारत के निर्यात में 40.5 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। चीन और वियतनाम के मोबाइल फोन निर्यात में करीब 50 फीसदी की कमी को भारत ने पूरा किया है यानी चीन और वियतनाम के मोबाइल फोन निर्यात में जितनी गिरावट आई है, उसमें से करीब 50 फीसदी निर्यात की हिस्सेदारी भारत के हिस्से में आई है। स्मार्टफोन प्रोडक्शन-लिंकड इंसैटिव (पीएलआई) योजना की घोषणा चीन की स्पन्दाई चैन में हो रहे बदलाव के मद्देनजर की गई थी। रिपोर्ट में एक अधिकारी के हवाले से बताया गया है कि इसके नतीजे दिखने लगे हैं। चीन मोबाइल फोन का टॉप निर्यातक बना हुआ है, लेकिन भारत भी उसके बराबर में आता दिख रहा है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार (आईटीसी) के आंकड़ों के मुताबिक चीन का मोबाइल फोन निर्यात वित्त वर्ष 2023 में 136.3 अरब डॉलर से घटकर वित्त वर्ष 2024 में 132.5 अरब डॉलर रह गया, जो 2.8 फीसदी की कमी है। इसके कुल निर्यात में 3.8 अरब डॉलर की गिरावट आई। वियतनाम का मोबाइल निर्यात भी वित्त वर्ष 2023 में 31.9 अरब डॉलर से घटकर वित्त वर्ष 2024 में 26.27 अरब डॉलर पर आ गया है, जो 17.6 फीसदी की कमी या कुल निर्यात में 5.6 अरब डॉलर की गिरावट है। दोनों देशों के निर्यात में मिलाकर कुल कमी 9.4 अरब डॉलर रही। भारत का मोबाइल फोन निर्यात वित्त वर्ष 2024 में 40 फीसदी से बढ़कर 15.6 अरब डॉलर हो गया। ये वित्त वर्ष 2023 में 11.1 अरब डॉलर था, यानी 4.5 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई है।

शेयर बाजार तेजी के साथ बंद

सेंसेक्स 443 अंक, निफ्टी 131 अंक ऊपर आया

आईटी, धातु और वित्तीय शेयरों में आया उछाल

मुम्बई । आईटी, धातु और वित्तीय शेयरों में आये उछाल से घरेलू शेयर बाजार सोमवार को तेजी के साथ बंद हुआ। सप्ताह के पहले ही कारोबारी दिन दुनिया भर से मिले-जुले संकेतों के बाद भी लिवाली (खरीददारी) हावी होने से बाजार में तेजी आई है। दिन भर के कारोबार के बाद तीस शेयरों वाला बीएसई मानक सूचकांक संसेक्स 443.46 अंक करीब 0.56 फीसदी की बढ़कर 79,476.19 अंक पर बंद हुआ। वहीं दूसरी ओर पचास शेयरों वाला नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 131.35 अंक तकरीबन 0.55 फीसदी उपर आकर अंत में 24,141.95 अंक पर बंद हुआ। आज कारोबार के दौरान संसेक्स में 30 शेयरों में से 20 शेयर लाभ के साथ ही ऊपर आये। टेक महिंद्रा, अल्ट्राटेक सीमेंट, बजाज फाइनेंस, एचयूएल और टीसीएस सबसे अधिक लाभ वाले शेयर रहे। वहीं इंफोसिस, जेएसडब्ल्यू

स्टील, एचडीएफसी बैंक, टाटा मोटर्स, आईटीसी, आईसीआईसीआई बैंक, टाटा टाइटन, मारुति, एचसीएल टेक, नेस्ते इंडिया, भारतीय एयरटेल, एशियन पेट्स, एमएंडएम, टाटा स्टील और कोटक बैंक के शेयर भी लाभ के साथ बंद हुए। वहीं दूसरी ओर संसेक्स के 30 शेयरों में 10 शेयर नुकसान के साथ ही नीचे आये हैं। इसमें एनटीपीसी, एसबीआई, सन फार्मा, एलएंडटी और इंडसइंड बैंक संसेक्स के सबसे अधिक नुकसान वाले पांच शेयर रहे। इसके अलावा, बजाज फिनसेव, पावर ग्रिड, रिलायंस, एक्सिस बैंक और अदाणी पोर्ट्स के शेयर भी नीचे आये। बाजार जानकारों के अनुसार अमेरिकी पीसीई मुद्रास्फीति में कमी के साथ सितंबर में फेंक द्वारा दर में कटौती की उम्मीद बढ़ने से घरेलू बाजार में तेजी की उम्मीद से भी आईटी शेयरों में उछाल आया। वहीं दूसरी ओर व्यापक सूचकांक इंट्र-डे कारोबार में रिफाई ऊंचाई पर पहुंच गया। बीएसई मिडकैप इंडेक्स 1.11 फीसदी बढ़कर बंद हुआ और अपने शीर्ष स्तर 46,696 के करीब पहुंच गया। वहीं बीएसई स्मॉलकैप इंडेक्स भी 1.58 फीसदी बढ़कर बंद

हुआ। इससे पहले आज सुबह बाजार सपाट शुरूआत हुई। सप्ताह के पहले ही कारोबार दिन दुनिया से प्राप्त मिले-जुले संकेतों से 30 शेयरों वाला बीएसई संसेक्स 44 अंक बढ़कर 79,077 के स्तर पर खुला। वहीं पचास शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 50 इंडेक्स 0.04 फीसदी की हल्की बढ़त के साथ 24,019 पर खुला। दुनिया के बाजारों की बात करें तो एशिया-पैसिफिक बाजारों में अलग-अलग प्रकार का कारोबार देखने में आया। एशियाई बाजारों की बात करें तो जापान का निक्केई 225 0.42 फीसदी बढ़ा जबकि व्यापक टॉपिक्स इंडेक्स 0.52 फीसदी बढ़ा। दूसरी ओर दक्षिण कोरिया का कोसमी 0.27 फीसदी नीचे आया, हालांकि कोस्टैक 0.79 फीसदी बढ़ा। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के एसएंडपी/एसएक्स 200 में 0.49 फीसदी की गिरावट रही। अमेरिकी बाजार में गिरावट रही। एसएंडपी 500 में 0.41 फीसदी की गिरावट आई, जबकि नैसैक कंपोजिट में 0.71 फीसदी की गिरावट रही।

चीनी इंजीनियरों के लिए वीजा मांग रहा अडानी ग्रुप

नई दिल्ली :

समझा जाता है कि अडानी समूह के सौर विनिर्माण कारोबार ने चीन से करीब 30 इंजीनियरों को लाने के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी मांगी है। बुनियादी ढांचे से लेकर खनन क्षेत्र वाले इस समूह के लिए ए इंजीनियर सौर उपकरणों की दमदार और स्वदेशी आपूर्ति श्रृंखला बनाने में मदद कर सकते हैं। कंपनी ने अपनी प्रस्तुतियों में आठ विदेशी साझेदारों का उल्लेख किया है। ये सभी चीन के हैं और मूल उपकरण विनिर्माता (ओईएम) तथा आपूर्ति श्रृंखला विक्रेता हैं। कंपनी ने वित्त वर्ष 2021-22 में 591 करोड़ रुपए के और वित्त वर्ष 2022-23 में 180 करोड़ रुपए के चीनी उपकरणों का आयात किया है। अडानी सोलर की सौर विनिर्माण इकाई मुंद्रा सोलर टेक्नोलॉजी लिमिटेड (एमएसटीएल) ने साल 2027 तक 10 गीगावॉट की एकीकृत सौर विनिर्माण क्षमता निर्माण का लक्ष्य रखा है। सरकार को दी गई

कंपनी की सूचना के अनुसार यह कारखाना गुजरात के कच्छ में 25,114 करोड़ रुपए के निवेश से लगाया जा रहा है। मुंद्रा सोलर केंद्र सरकार की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना के तहत भी पात्र है। पीएलआई योजना के तहत यह चार गीगावॉट सौर मांड्यूल विनिर्माण लागूएगी। इसका इंगट, वेफर और सेल (सौर मांड्यूल/पैनल हिस्से) विनिर्माण पीएलआई में शामिल नहीं है। फरवरी में अडानी सोलर ने अपनी सौर विनिर्माण इकाई में काम पर रखे जाने वाले 15 चीनी नागरिकों के लिए एसी ही उपकरणों के निर्माण में लगे हुए हैं। इन फर्मों के इंजीनियर उत्पाद इकट्टाया लगाने, मौजूदा इकाइयों में उत्पादन बढ़ाने और भारतीय कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने में अडानी की मदद करेंगे। भारत में उनके रहने की अवधि छह महीने से एक वर्ष तक की है। चीन के इंजीनियरों को वीजा मंजूरी के लिए कंपनी ने तर्क दिया है कि ऐसी सौर इकाई लगाने के लिए भारत में विशेषज्ञता की कमी है।



मेक इन इंडिया पहल का हिस्सा बताया है। अडानी सोलर की ओर से सूचीबद्ध आठ चीनी विक्रेता सिलिकॉन सेल, फोटोडिफ्यूजिंग उपकरण, वेफर विनिर्माण, सेमीकंडक्टर और सौर उपकरण आपूर्ति श्रृंखला के लिए जरूरी ऐसी ही उपकरणों के निर्माण में लगे हुए हैं। इन फर्मों के इंजीनियर उत्पाद इकट्टाया लगाने, मौजूदा इकाइयों में उत्पादन बढ़ाने और भारतीय कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने में अडानी की मदद करेंगे। भारत में उनके रहने की अवधि छह महीने से एक वर्ष तक की है। चीन के इंजीनियरों को वीजा मंजूरी के लिए कंपनी ने तर्क दिया है कि ऐसी सौर इकाई लगाने के लिए भारत में विशेषज्ञता की कमी है।

क्या सरकार निवेशकों को कैपिटल गेन टैक्स में देगी राहत?

विजनेस डेस्क :

नई एनडीए सरकार केंद्रीय बजट 2024 (पूर्ण बजट) पर जोर-शोर से काम कर रही है। इस बजट से इस बार हर किसी को काफी उम्मीदें हैं। जानकारों को उम्मीद है कि इस बार केंद्रीय बजट में सरकार निवेशकों को पूंजीगत लाभ कर (कैपिटल गेन टैक्स) के मामले में थोड़ी राहत जरूर दे सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि होल्डिंग अवधि को सुव्यवस्थित करने के लिए पूंजीगत लाभ व्यवस्था को तर्कसंगत और मानकीकृत करने से दरों में एक रूपाता और दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ के लिए सूचीकरण के आधार वर्ष में बदलाव से निवेशकों को लाभ होगा। ऐसी

उम्मीदें हैं कि घरेलू इक्विटी और म्यूचुअल फंड में एक समान होल्डिंग अवधि शुरू करके पूंजीगत लाभ कर संरचना को सरल बनाया जाएगा। किस पर लगता है कैपिटल गेन टैक्स इनकम टैक्स कानून के हिसाब से, चल और अचल दोनों तरह की पूंजीगत संपत्तियों की बिक्री से होने वाले लाभ पर कैपिटल गेन टैक्स चुकाना होता है। अलग-अलग प्रकार की संपत्तियों - जैसे इक्विटी, ऋण और रियल एस्टेट - पर अलग-अलग दरों और अवधियों के टैक्स लगाया जाता है, जो यह निर्धारित करते हैं कि लाभ अल्पकालिक है या दीर्घकालिक। जानकारों को उम्मीद है कि सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों में प्रत्यक्ष निवेश और ऋण-उन्मुख म्यूचुअल फंड के जरिये समान उपकरणों में अप्रत्यक्ष निवेश का सरल बनाना होगा। फिलहाल सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों और शूच्य-कूपन बॉन्ड (सूचीबद्ध या गैर-सूचीबद्ध) में 12 महीने से अधिक के लिए प्रत्यक्ष निवेश को दीर्घकालिक निवेश माना जाता है। दूसरी तरफ अगर निवेश ऋण-उन्मुख म्यूचुअल फंड योजना के माध्यम से किया जाता है, तो दीर्घकालिक निवेश होने के लिए होल्डिंग अवधि 36 महीने तक बढ़ जाती है। अप्रैल 2023 के बाद इक्विटी की तरफ झुकाव एक्सपर्ट मानते हैं कि अगर लोन म्यूचुअल फंड निवेश के लिए दीर्घकालिक होल्डिंग अवधि को घटाकर 12 महीने कर दिया जाता है, तो यह दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर संरचना को सरल बनाकर निवेशकों के लिए कैटेगरी को आकर्षक बना देगा। अप्रैल 2023 के बाद निवेशकों के निवेश आवंटन में इक्विटी की तरफ झुकाव देखा गया है। एक्सपर्ट का कहना है कि हम निवेशकों को उनके निवेश सलाहकार की सलाह के आधार पर अपने पोर्टफोलियो में डेट इक्विटी मिक्स रखने में फायदा देख रहे हैं। यही वजह है कि डेट म्यूचुअल फंड के लिए कुछ टैक्स छूट की उम्मीद की जा सकती है। हम इक्विटी के लिए पूंजीगत लाभ कर पर यथास्थिति की उम्मीद करते हैं।

2000 रु के 97.87% नोट वापस आए, 7,581 करोड़ रुपए मूल्य के नोट अब भी लोगों के पास

मुंबई :

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सोमवार को कहा कि दो हजार रुपए मूल्य के 97.87 प्रतिशत नोट बैंकों में वापस आ गए हैं। चलन से हटाए गए केवल 7,581 करोड़ रुपए मूल्य के नोट अब भी लोगों के पास हैं। आरबीआई ने 19 मई 2023 को 2000 रुपए मूल्य के बैंक नोट को चलन से वापस लेने की घोषणा की थी। चलन में 2000 रुपए मूल्य के बैंक नोट का कुल मूल्य 19 मई 2023 को कारोबार की समाप्ति पर 3.56 लाख करोड़ रुपए था। यह 28 जून 2024 को कारोबार की समाप्ति पर घटकर 7,581 करोड़ रुपए रह गया। केंद्रीय बैंक ने बयान में कहा, 'इस प्रकार 28 जून 2024 तक 2000 रुपये के 97.87 प्रतिशत बैंक नोट बैंकों में वापस आ गए हैं। सात अक्टूबर 2023 तक 2000 रुपए के बैंक नोट को जमा करने और/या बदलने की सुविधा देश की सभी बैंक शाखाओं में उपलब्ध थी। 19 मई 2023 से 2000 रुपए के बैंक नोट को बदलने की सुविधा रिजर्व बैंक के 19 निर्गम कार्यालयों में उपलब्ध रही। आरबीआई के निर्गम कार्यालय नौ



अक्टूबर 2023 से लोगों और संस्थाओं से उनके बैंक खातों में जमा करने के लिए भी 2000 रुपए के नोट स्वीकार कर रहे हैं। इसके अलावा, लोग अपने बैंक खातों में जमा करने के लिए देश के किसी भी डाकघर से आरबीआई के किसी भी निर्गम कार्यालय में 2000 रुपए के बैंक नोट भेज रहे हैं। बैंक नोट को जमा/बदलने वाले आरबीआई के 19 कार्यालय अहमदाबाद, बंगलुरु, बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पटना और तिरुवनंतपुरम में हैं। अक्टूबर 2023 से 2000 रुपए के बैंक नोट को बदलने की सुविधा रिजर्व बैंक के 19 निर्गम कार्यालयों में उपलब्ध रही। आरबीआई के निर्गम कार्यालय नौ

जोमैटो को बड़ा झटका, मिला 9.45 करोड़ रुपए का जीएसटी नोटिस



नई दिल्ली ।

ऑनलाइन फूड डिलीवरी करने वाली कंपनी जोमैटो लिमिटेड को एक झटका लगा है। दरअसल, कंपनी को कर्नाटक के वाणिज्यिक कर (ऑडिट) के सहायक आयुक्त से 9.45 करोड़ रुपए का माल और सेवा कर (जीएसटी) मांग नोटिस मिला है। कंपनी ने बीएसई एक्सचेंज फाइलिंग में इस बात की जानकारी दी। कर्नाटक के टैक्स रेगुलेटर ने 5.01 करोड़ रुपए जीएसटी डिमांड किया है। लाइवमिंट की खबर के मुताबिक, फाइलिंग के अनुसार, इसे 3.93 करोड़ रुपए के ब्याज शुल्क और 50.19 लाख रुपए के जुर्माने के साथ चिह्नित किया जाएगा, जिससे कुल राशि 9.45 करोड़ रुपए हो जाएगी। खबर के मुताबिक, फाइलिंग में कंपनी ने बताया है कि कंपनी को जीएसटी रिटर्न और खातों के ऑडिट के तहत वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए टैक्स ऑर्डर प्राप्त हुआ है। बता दें, जोमैटो के शेयर शुक्रवार, 28 जून को ₹200.15 पर पिछले बंद की तुलना में 0.10 प्रतिशत बढ़कर ₹200.35 पर बंद हुए। कंपनी ने टैक्स नोटिस के जवाब में कहा कि हफ्ता मानाना है कि हमारे पास गुणा-दोष के आधार पर एक मजबूत मामला है। कंपनी उचित प्रक्रिया की समझ आदेश के खिलाफ अपील दायर करेगी। यह पहली बार नहीं है जब फूड डिलीवरी कंपनी को टैक्स नोटिस मिला है। जोमैटो को 2021 में गुरुग्राम के केंद्रीय माल और सेवा कर के अतिरिक्त आयुक्त से टैक्स नोटिस मिला था। उस समय की मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, उस नोटिस में कंपनी से ब्याज और जुर्माना शुल्क सहित ₹11.82 करोड़ का मुआतात करने की मांग की गई थी। कंपनी ने भी टैक्स नोटिस के खिलाफ अपील करने का रुख अपनाया।



ऑफिस
में कई बार हम कुछ ऐसा पहनकर चले जाते हैं जिससे हम उपहास या गॉसिपिंग का पात्र बन जाते हैं। शालीनता के साथ अगर आप ऑफिस में अपने आपको कैरी करती हैं तो आपको कपड़ों को लेकर कभी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। आपके ड्रेसिंग सेंस की सब तारीफ करेंगे

ऑफिस में क्या पहनें... जरा ध्यान दें

हर चीज चाहे वो कपड़े ही क्यों न हों, समय और जगह के माकूल होने चाहिए, नहीं तो वो बुरे लगने लगते हैं। यह बात यूं तो हर जगह लागू होती है, पर अगर आप वर्किंग वुमन या गर्ल हैं तो फिर इस बात पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ऑफिस में कई बार हम कुछ ऐसा पहनकर चले जाते हैं जिससे हम उपहास या गॉसिपिंग का पात्र बन जाते हैं। शालीनता के साथ अगर आप ऑफिस में अपने आपको कैरी करती हैं तो आपको कपड़ों को लेकर कभी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। आपके ड्रेसिंग सेंस की सब तारीफ करेंगे, सो अलग।

ट्राउजर, जीन्स में फोन पिन न करें

अगर आप इंजीनियर या आर्किटेक्ट जैसे फील्ड वर्क में हैं तो ट्राउजर, जीन्स आदि में फोन पिन करना ठीक भी है, लेकिन ऑफिस में यह स्टाइल सही नहीं है। यह देखने में बिल्कुल चाइल्डिश लगता है। मोबाइल फोन को या तो अपने पर्स में या फिर हाथ में ढंग से कैरी करें।

रिक्न रिवीलिंग ड्रेस को ना

बहुत ज्यादा रिक्न रिवीलिंग ड्रेस पहन कर भी ऑफिस में आना अच्छी बात नहीं है। ऑफिस में इस तरह की ड्रेस न केवल खराब लगती है, बल्कि छवि पर भी इसका खास असर पड़ता है।

लिविंग रूम

को बनाएं जानदार

कपड़े प्रेस करने वाले आयरन में जंग लग जाती है, जिसे आप नमक के घोल से साफ कर सकती हैं।

लिविंग रूम में कई तरह के फूलों के गुलदस्ते भी रखें। गुलदस्ते के लिए आप कृत्रिम के साथ-साथ प्राकृतिक फूलों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लिविंग रूम को सजाने का यह आसान तरीका है। लिविंग रूम में आप अपनी दीवार के लिए सफेद और मटैलिक सिल्वर के कॉन्बिनेशन का इस्तेमाल कर सकती हैं।



बड़े काम का नमक

अगर कांच के गिलास साफ करने हैं तो उन्हें नमक वाले पानी के घोल में दस मिनट के लिए भिगो कर रखें और फिर उन्हें नींबू और साफ पानी से धो लें। कपड़े प्रेस करने वाले आयरन में जंग लग जाती है, जिसे आप नमक के घोल से साफ कर सकती हैं। महीने में एक बार नमक के घोल से चांदी का सामान साफ करें। चांदी के गहनों को नमक वाले घोल में 15 मिनट के लिए भिगो कर बाद में साफ पानी से धो लें।



माना आजकल बहुत ज्यादा प्रदूषण हो गया है और चेहरे को हमेशा साफ रखना चाहिए, पर इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आप हर घंटे ही अपना चेहरा धोते रहें। दिन में चेहरे को दो बार धोना चेहरे को साफ रखने के लिए पर्याप्त है। एक बात का ध्यान रखें कि बार-बार चेहरे को धोने से चेहरे की त्वचा में मौजूद प्राकृतिक तेल खत्म हो जाता है और त्वचा अपने आप रूखी हो जाती है। जिससे रिक्लस पड़ने की आशंका रहती है।

वजन कम करने की चाहत

आजकल तो वजन कम करने का एक ट्रेंड ही चल पड़ा है। कई बार तो कुछ महिलाएं अपना वजन इतना ज्यादा कम कर लेती हैं कि बाद में उन्हें शरीर को सही रखने के लिए वजन बढ़ाना पड़ता है। ऐसा करने से त्वचा अपनी कसावट खो देती है। जिस वजह से त्वचा लटकती नजर आती है और उसका कसावट कम हो जाता है।

बहुत ज्यादा मुंह धोना

माना आजकल बहुत ज्यादा प्रदूषण हो गया है और चेहरे को हमेशा साफ रखना चाहिए, पर इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आप हर घंटे ही अपना चेहरा धोते रहें। दिन में चेहरे को दो बार धोना चेहरे को साफ रखने के लिए पर्याप्त है। एक बात का ध्यान रखें कि बार-बार चेहरे को धोने से चेहरे की त्वचा में मौजूद प्राकृतिक तेल खत्म हो जाता है और त्वचा अपने आप रूखी हो जाती है। जिससे रिक्लस पड़ने की आशंका रहती है।

स्ट्रॉ से पेय पदार्थ पीना

आप इसे फैशन मानें या फिर कुछ और, पर अधिकतर महिलाएं सॉफ्ट ड्रिंक्स आदि को पीने के लिए स्ट्रॉ का उपयोग ही करती हैं, पर स्ट्रॉ का उपयोग करते वक्त उन्हें यह बिल्कुल ख्याल नहीं रहता है कि ऐसा करने से होंठों के चारों ओर की त्वचा सिकुड़ जाती है और इससे होंठों के आसपास की त्वचा में झुर्रियों की आशंका होती है।

बढ़ती है आपकी उम्र

कॉन्टेक्ट लेंस पहनना

कॉन्टेक्ट लेंस का कॉन्सेप्ट उन लोगों के लिए आया था, जिनकी आंखों में बहुत ज्यादा पावर वाला चश्मा होता था, लेकिन आज मामला थोड़ा उल्टा है। आजकल बाजार में हर रंग के कॉन्टेक्ट लेंस मिलते हैं, जिन्हें अक्सर लड़कियां फैशन स्टेटमेंट के चलते कैरी करती हैं। हमेशा कॉन्टेक्ट लेंस का इस्तेमाल करने से आंखों को चोट भी पहुंच सकती है और आंखों के आसपास की त्वचा चूक नजुक होती है तो झुर्रियां पड़ने की आशंका भी होती है।

आंखें चक कराएं

यूं तो कायदे से साल में एक से दो बार आंखों का चेकअप कराना बहुत ही जरूरी है, पर अधिकतर महिलाएं ऐसा बिल्कुल नहीं करतीं। ऐसे में आंखों में धैगान की समस्या हो सकती है और इस कारण आपकी खूबसूरती भी जाती रहेगी और दोनों भौंहों के बीच झुर्रियों की समस्या भी हो सकती है, इसलिए समय पर नियमित रूप से चेकअप कराना बहुत फायदेमंद रहता है।

ज्यादा झाड़विलिंग से बचें

आपमें से अधिकतर महिलाएं ये सोचती होंगी कि कार में झाड़विलिंग करते वक्त वो सूज की अल्ट्रा वायलेट किरणों से बची रहती हैं।



शॉर्ट कपड़े न ही पहनें तो अच्छा है

ऑफिस में कोई भी ड्रेस पहनने के लिए कुछ नियम-कायदे होते हैं। ऐसे में आप उन्हें फॉलो न करके शॉर्ट कपड़े पहन कर अगर ऑफिस आती हैं तो एक तो यह ऑफिस डेकोरम के खिलाफ बात होगी, दूसरे आप बिना मतलब के लोगों के बीच चर्चा का विषय बन जाएंगी। इसलिए शॉर्ट ड्रेसिस न ही पहनें तो ज्यादा सही रहेगा।

बहुत ज्यादा टाइट और पतला कपड़ा

बहुत-सी महिलाएं यह मानती हैं कि फिटिंग के कपड़े पहनने से एक कॉन्फिडेंस आता है, यह कुछ हद तक सही है। लेकिन अगर आप ऑफिस में फिटिंग के कपड़े की जगह बिल्कुल ही टाइट फिटिंग और बेहद पतले स्टाफ के कपड़े पहन कर आती हैं तो हो सकता है कि आप लोगों के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन का पार्ट बन जाएं, जो पॉजिटिव वे में तो कम पर, निगेटिव वे में ज्यादा होगा।

हाई हिल्स पहन कर आना

माना कि हाई हिल्स पहनना आपको पसंद है, लेकिन ऑफिस में ये परफेक्ट नहीं। हिल्स आवाज बहुत करती हैं, जो ऑफिस में अन्य लोगों को काम करने में बाधा पहुंचा सकती है। इसलिए अगर आपको हील पहननी भी हैं तो प्लैट हील या फिर कम हील की सैंडल्स पहनें या फिर प्लैट स्टाइलिश स्लीपर पहनें, पर जो भी पहनें, वो आपकी ड्रेस के मुताबिक हो, यह जरूर देख लें।

ज्यादा चटकीले रंग के कपड़े

ऑफिस में सिम्पल और सोबर रंग के कपड़े पहनना ज्यादा सही रहता है। कुछ महिलाएं होती हैं, जो ऑफिस में बहुत ज्यादा कलरफुल और चटकीले रंग के कपड़े पहन कर आती हैं। उनका यह ड्रेसिंग सेंस न तो ऑफिस के लिहाज से अच्छा होता है और न ही लोग उनके ड्रेसिंग सेंस की तारीफ करते हैं। हां उल्टे, वो मजाक का पात्र जरूर बन जाती हैं।

नहीं दिखे स्पैगिटी की स्ट्रिप

अंडर समीज या स्पैगिटी की स्ट्रिप अगर बार-बार फिसल कर आपके कुर्ते आदि की बाहों के नीचे आती हैं तो यह बहुत ही इम्बेसिंग मुमैंट हो सकता है आपके लिए। इसलिए ऐसे कपड़े बिल्कुल भी न पहनें, जिनकी वजह से आपको शर्मिंदा होना पड़े पूरे ऑफिस में।

ट्रेंडी प्रिंटेड ब्लेजर

मौसम को देखते हुए ब्लेजर और ट्रेंड को देखते हुए प्रिंटेड। यदि इन दोनों चीजों को साथ मिलाया जाए, तो जो मसाला तैयार होगा, वही लेटेस्ट ट्रेंड होगा। डिजाइनर इसी वजह से प्रिंटेड ब्लेजर ला रहे हैं।

लार्ज प्रिंट

व्हाइट बैकग्राउंड के साथ यदि ब्ल्यू लार्ज प्रिंट आजमाया जाए, तो यह सभी को पसंद आएगा। बूटेदार प्रिंट इस मामले में सबसे ज्यादा चलन में है। जारा इंडिया पर इसकी कीमत 4790 रूपए है।

मोनो प्रिंटेड

यदि आपको मल्टीकलर प्रिंट पसंद नहीं, तो वर्कप्लेस पर इसे आजमाएं। ये कई डिजाइन्स में अवेलेबल हैं। कूज ऑनलाइन स्टोर पर इसकी प्राइस 945 रूपए है।



वूलन चैक्ट

इसे किसी भी तरह की रेगुलर ड्रेस के साथ आजमाया जा सकता है। बीकाइंड ब्रांड के इस ब्लेजर की प्राइस 1799 रूपए से शुरू है।

लेपर्ड डिटेल्स

आप यदि इसे किसी पार्टी में पहन रही हैं, तो लेपर्ड डिटेल्स को आजमा सकती हैं। साडी पर भी ये अच्छे लगते हैं। विवेशियस इन वॉग ब्रांड ब्लेजर की प्राइस 2200 रूपए है।

पिंक फ्लॉरल

यदि आप पलॉरल प्रिंट ही आजमाना चाहती हैं, तो पिंक फ्लॉरल को आजमाइए। कूज ऑनलाइन स्टोर पर प्राइस 1185 रूपए है।

कैजुअल प्रिंटेड

सिम्पल और सोबर ब्लेजर के लिहाज से कैजुअल प्रिंटेड ब्लेजर बेस्ट ऑप्शन है। इन्हें किसी भी मौके पर कैरी किया जा सकता है। स्टाइलर्टोस पर प्राइस 1399 रूपए से शुरू है।

ब्राइट होलोग्राफ

यदि आप कॉलर लैस ब्लेजर पसंद करती हैं, तो यह ब्राइट ब्लेजर आपको पसंद आएगा। ग्लेम एंड लक्स ब्रांड के ब्लेजर की कीमत 1999 रूपए है।



तापी नदी में पानी आने से

काँजवे का स्तर ६ मीटर पहुंचते ही काँजवे वाहन व्यवहार के लिए बंद किया गया

क्रांति समय
www.krantisamay.com
www.guj.krantisamay.com
www.epaper.krantisamay.com
www.rti.krantisamay.com

सूरत, दक्षिण गुजरात में मेघमेहर देखने को मिल रहा है. सूरत जिले में पिछले ३ दिनों से भारी बारिश हो रही है. सूरत शहर में जारी बारिश से विपर कम काँजवे, जहां तापी नदी बहती है, वह भी उफान पर आ गया. जिसके चलते वाहन यातायात के लिए बंद कर दिया गया.

तापी नदी में नये पानी के आगमन से दोनों किनारों पर

बहते पानी के दृश्य दिखाई दे रहे हैं. मानों काँजवे का मनोरम दृश्य देखने को मिल रहा हो. जैसे ही काँजवे का स्तर ६ मीटर तक पहुंच गया, तंत द्वारा तुरंत बंद करने का निर्णय लिया गया. तापी नदी के बढ़ते जल स्तर के कारण एहतियात के तौर पर काँजवे को वाहनों के आवागमन के लिए बंद कर दिया गया है. सीजन में पहली बार काँजवे बंद कर दिया गया. जलस्तर कम होने के बाद ही काँजवे शुरूकिया जाएगा.

काँजवे अडाजण रांदेर से सिंगणपोर तक का सबसे

व्यस्त मार्ग है. यहां से प्रतिदिन हजारों वाहन चालक गुजरते हैं. सुबह से ही काँजवे बंद होने से वाहन चालक परेशान हुए. वाहन चला रहे कई लोगों को पता ही नहीं चला कि काँजवे बंद कर दिया गया है. एक ओर जहां चौक बाजार से होकर सिंगणपोर जाना मुश्किल हो रहा है. क्योंकि, मेट्रो का काम चलने के कारण रास्ता बंद है. अधिकांश वाहन चालकों को दाभोली चार रास्ता और जहांगीरपुरा को जोड़ने वाले पुल का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा.



फुल स्पीड में चलते समय ड्राइवर ने खोया नियंत्रण, ५ घायल

क्रांति समय
www.krantisamay.com
www.guj.krantisamay.com
www.epaper.krantisamay.com
www.rti.krantisamay.com

सूरत, वराछ इलाके में देर रात एक एसटी बस ड्रिवाइडर में घुसकर पलट गई. हादसे के बाद यात्रियों से भरी बस पलट गई और चिल्लाहट मच गई. कुछ यात्री घायल हो गए और उन्हें स्मीमेर अस्पताल ले जाया गया. गौरतलब है कि इस बस के ड्राइवर के भी नशे में होने की चर्चा है. फिलहाल इस मामले में पुलिस द्वारा आगे की जांच की जा चुकी है.

जानकारी के मुताबिक, वापी से आ रही एसटी बस रविवार रात सूरत से दाहोद जा रही थी.

इसी दौरान किरण हॉस्पिटल से अलकापुरी ब्रिज पार कर नीचे उतरते समय बस पूरी स्पीड में थी. इसी दौरान बस चालक ने स्टेयरिंग से नियंत्रण खो दिया और बस सड़क के बीचो बीच ड्रिवाइडर पर चढ़ गई. बस

स्मीमेर अस्पताल ले जाया गया. कोई भी यात्री गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ. बताया जा रहा है कि बस ड्राइवर नशे में था. हालांकि पुलिस द्वारा मामले की आगे की जांच की जा रही है. देर रात एसटी बस

घायलों के नाम

मधुबेन बजरंग परमार (उम्र ४५, निवासी हालोल दाहोद)
किजल आकाश राठोड़ (उम्र २७, निवासी हालोल)
हिना नेवास कायल (उम्र ४४, निवासी सेलवास)
वीर सिंह धूलियाभाई पणरा (उम्र ४५, निवासी हालोल दाहोद)
रमन भूराभाई रागर्जी (उम्र ३८, निवासी दाहोद)

ड्रिवाइडर से ५ से १० फीट उमर चली गई. अचानक हुए इस हादसे से बस में सवार यात्रियों में चिल्लाहट मच गई. बस में सवार कुछ यात्री भी घायल हो गए. उन्हें तुरंत

हादसा होने पर सूरत के मेयर दक्षे मवानी भी घटनास्थल पर पहुंचे. इसके साथ ही उन्होंने घायल यात्रियों से भी बातचीत की.



डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण की गाड़ी अचानक ही सड़क पर हवाई जहाज की तरह आगे से उमर उठ गई

क्रांति समय
www.krantisamay.com
www.guj.krantisamay.com
www.epaper.krantisamay.com
www.rti.krantisamay.com

सूरत, पिछले दो दिनों से शहर में मेघमेहर देखी जा रही है. इसी बीच शहर में डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण टेंपो जो कतारगाम-अमरोली तापी ब्रिज के पास से गुजर रहा था. टेंपो बीच रोड में आगे से उमर उठ गया. सामने आया कि टेंपो के पिछले हिस्से में कूड़ा अधिक मात्रा में भरा होने के कारण यह घटना घटी. टेंपो चालक टेंपो को उसी हालत में छोड़कर भाग निकला. हालांकि, सौभाग्य से

इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ. इस घटना का वीडियो भी सामने आया. वीडियो में पाया गया कि रोड से गुजर रहा टेंपो अचानक ही बीच रोड में उमर से उठ गया. अनुमान लगाया जा रहा है कि टेंपो

ओवरलोड होने के कारण आगे से उमर उठा. अचानक बीच रोड में टेंपो उमर उठने के कारण अन्य गुजर रहे वाहनों को परेशानी हुई. उधर, टेंपो चालक टेंपो को उसी हालत में छोड़कर चला गया.



चालू बारिश में सड़क पर बोलेरो के

पुलिस ने किया गिरफ्तार

क्रांति समय
www.krantisamay.com
www.guj.krantisamay.com
www.epaper.krantisamay.com
www.rti.krantisamay.com

सूरत, सूरत में एक युवक की बोलेरो पिकअप गाड़ी पर खतरनाक सवारी का वीडियो वायरल हुआ था. जिसे लेकर भेस्तान पुलिस ने जांच शुरू की और इस घटना में दो लोगों को गिरफ्तार किया है. युवकों के पकड़े जाने के बाद दोनों ने माफी मांगी.

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक युवक सफेद रंग की बोलेरो पिकअप के बोनट पर बैठा हुआ था. साथ ही एक अन्य युवक गाड़ी चला



रहा था. यह वीडियो भेस्तान इलाके का होने की बात सामने आई. जिसके बाद भेस्तान पुलिस ने पूरे मामले की जांच की. भेस्तान पुलिस ने इस घटना में ड्राइवर का काम करने वाले ३२ वर्षीय शाहख सफी शेख और २५ वर्षीय अनिल राजाराम कांबले को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की. थोड़ी सी लापरवाही भी इस युवक पर भारी पड़ सकती थी. हालांकि, यह वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की. इस बीच इन दोनों युवकों ने माफी भी मांगी. लोगों से इस तरह के खतरनाक वीडियो न बनाने की भी अपील की गई.

न्यू सिविल अस्पताल में नर्सिंग एसोसिएशन ने मनाया 'राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस', उपस्थित डॉक्टरों को किया गया सम्मानित

क्रांति समय
www.krantisamay.com
www.guj.krantisamay.com
www.epaper.krantisamay.com
www.rti.krantisamay.com

सूरत, न्यू सिविल अस्पताल में सोमवार को नर्सिंग एसोसिएशन द्वारा 'राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस' के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में २०० से अधिक सिविल डॉक्टरों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया. नर्सिंग काउंसिल के इकबाल कड़ीवाला ने इस अवसर पर कहा कि 'राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस' उन डॉक्टरों की सेवा और समर्पण का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है, जो जन्म से पहले और जन्म के बाद बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य का खयाल रखते हैं. उन्होंने कहा कि सफेद एप्रन पहनने वाले डॉक्टर मानव जाति के लिए वरदान हैं, जिन्होंने कोरोना महामारी के दौरान



अपने दृढ़ विश्वास से पूरी दुनिया को बचाया. आगे कहा कि दक्षिण गुजरात का सबसे बड़ा न्यू सिविल अस्पताल लोगों के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रख रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि सभी जख्मतमंद लोगों को डॉक्टरों और नर्सिंग

स्टाफ द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं. उन्होंने मरीज और डॉक्टर के बीच आपसी संबंधों पर भी बात करते हुए कहा कि डॉक्टर की एक मुस्कान मरीज के लिए दवा से भी ज्यादा कारगर होती है. उन्होंने कोरोना

महामारी, रेल और प्लेग जैसी आपदाओं के दौरान मानव जीवन को बचाने वाले डॉक्टरों की सेवाओं की भी सराहना की. इस अवसर पर चिकित्सा अधीक्षक डॉ. प्रीति कपाड़िया, आर.एम.ओ. डॉ. केतन

नायक, शासकीय मेडिकल कॉलेज की डीन डॉ. रागिनी वर्मा, अतिरिक्त अधीक्षक डॉ. धारीती परमार, टी.बी. छाती विभाग की प्रमुख डॉ. पारुष वडगामा, डॉ. के.एन. भट्ट, मेडिसिन विभाग के डॉ. हरि मेमन, हड्डि विभाग के डॉ. गुणवंत परमार, रेडियोलॉजिस्ट डॉ. पूर्वी देसाई, दंत चिकित्सा विभाग के डॉ. जिगिशा पारटिया, बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. बिनोदिनी महेंद्रसिंह चौहान, शारीरिक चिकित्सा विभाग के डॉ. कमलेश दवे और डॉ. अश्विन वसावा, और मनोचिकित्सा विभाग की डॉ. रितुभरा मेहता सहित सभी विभागों के रेजिडेंट डॉक्टरों को सम्मानित किया. इस कार्यक्रम में स्थानीय एसोसिएशन के अध्यक्ष अश्विन पंड्या, सिविल अस्पताल के नीलेश लाडिया सहित सिविल डॉक्टर, मुखिया और कर्मचारी उपस्थित थे.

उधना रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर दो-तीन की जमीन धसी,

तत्काल मरम्मत शुरूकिया गया

क्रांति समय
www.krantisamay.com
www.guj.krantisamay.com
www.epaper.krantisamay.com
www.rti.krantisamay.com

सूरत, मानसून शुरू होते ही उधना रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर दो-तीन पर जमीन का एक हिस्सा धस गया. कुछ जगहों पर एक से डेढ़ फीट तक ज्वमिन धसी दिखी. कुछ समय पहले स्टेशन विकास के तहत प्लेटफॉर्म नंबर दो और तीन को बंद करने के बाद फिर संचालित किया गया था. दोनों चबूतरों के कुछ हिस्सों को तोड़कर दोबारा बनाया गया था. लेकिन काम ठीक तरीके से नही होने से पहले ही बारिश में प्लेटफॉर्म का कुछ हिस्सा धंस गया. जब तंत को इसकी

जानकारी हुई तो उन्होंने अधिकारियों को सूचित किया कि कई जगहों पर जमीन का हिस्सा धस गया है, तो कई जगहों पर दरारे आई है. प्लेटफॉर्म को नुकसान होने की जानकारी मिलते ही रेलवे अधिकारी तुरंत दौड़ पड़े. टेकेदार के साथ मिल कर तुरंत मरम्मत कार्य शुरूकराया गया. प्लेटफॉर्म संख्या दो-तीन पर ट्रेनों का आवागमन अधिक होने के कारण प्लेटफॉर्म को बंद नहीं किया गया. यात्रियों की आवाजाही के बीच मरम्मत का काम किया गया. यहां बता दें कि कुछ समय पहले उधना रेलवे स्टेशन के विकास के तहत दोनों प्लेटफॉर्म को ९० दिनों के लिए बंद किया गया था.



लिंबायत में स्टेट मॉनिटरिंग सेल की रेड में शराब की बोतले जब्त कर

तीन आरोपी को वांछित घोषित किया गया

क्रांति समय
www.krantisamay.com
www.guj.krantisamay.com
www.epaper.krantisamay.com
www.rti.krantisamay.com

सूरत, सूरत में स्थानीय पुलिस सो रही हो और स्टेट मॉनिटरिंग सेल की टीम शराब की भारी मात्रा पकड़ रही हो ऐसी अनेक घटनाएं सामने आती रहती हैं. एक बार फिर स्टेट मॉनिटरिंग सेल की टीम ने लिंबायत इलाके में १२०० से ज्यादा शराब की बोतलें जब्त कर

कानूनी कार्रवाई की है. साथ ही तीन आरोपियों को वांछित घोषित किया है. स्टेट मॉनिटरिंग सेल टीम की कार्रवाई को लेकर स्थानीय पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं. क्या स्थानीय पुलिस के नजर में ये शराब के अड्डे नही आते है या स्थानीय पुलिस के आँखों के निचे से ये सब हो रहा है? स्टेट मॉनिटरिंग सेल की टीम ने लिंबायत इलाके में रतन चौक

के पास छपा मारकर १२५२ बोतल शराब जब्त की. पुलिस ने दो वाहनों को जब्त किया है. इसी के साथ कुल १,८९,००० मूल्य की धनराशि जब्त कर पुलिस द्वारा आगे की जांच की जा रही है. पुलिस ने शराब की मात्रा के मामले में तीन आरोपियों को वांछित घोषित किया है. जिसमें लिंबायत के मुन्ना लंगड़ा (मुख्य आरोपी) को वांछित घोषित किया गया है.

